नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 194
दि. 18.04.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में महाब्रेक, दो-तिहाई बहुमत से चूकी सरकार

नई दिल्ली में संसद के निचले सदन लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़ा संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 उस समय गिर गया, जब सरकार आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने में असफल रही। यह घटनाक्रम न केवल मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर चल रही बहस को भी नई दिशा दे गया है।

मत विभाजन के दौरान विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 मत डाले गए। कुल 528 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इसे पारित कराने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी। आवश्यक आंकड़े से काफी पीछे रह जाने के कारण विधेयक गिर गया। यह पहली बार माना जा रहा है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने में विफल रही है।

इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना था, जिसे 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना थी। हालांकि, विधेयक के साथ जुड़े परिसीमन और अन्य प्रावधानों को लेकर विपक्षी दलों ने गंभीर आपत्तियां जताईं, जिसके चलते व्यापक समर्थन नहीं मिल सका।

वोटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू ने स्पष्ट किया कि जब मूल संविधान संशोधन विधेयक ही पारित नहीं हो पाया, तो उससे जुड़े अन्य विधेयक—

'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026'—को आगे बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे यह साफ हो गया कि फिलहाल महिला आरक्षण को लागू करने की पूरी प्रक्रिया ठप पड़ गई है।

इससे पहले सदन में करीब 21 घंटे तक लंबी और गहन बहस चली, जिसमें 130 सांसदों ने हिस्सा लिया। इनमें 56 महिला सांसद भी शामिल थीं, जिन्होंने अपने-अपने दृष्टिकोण रखे। बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसमें विधेयक के स्वरूप, क्रियान्वयन और इसके संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा हुई।

चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने 'अगर-मगर' और 'किंतु-परंतु' के जरिए इस विधेयक का विरोध किया और वास्तविकता में महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ खड़ा रहा। शाह ने कहा कि देश की महिलाएं सब देख रही हैं और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं।

विधेयक गिरने के बाद संसद परिसर में एनडीए की महिला सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यह केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और समान प्रतिनिधित्व से जुड़ा सवाल है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधा डालने का आरोप लगाया।

दूसरी ओर, विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए अलग ही तर्क प्रस्तुत किए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह केवल महिला आरक्षण का मामला नहीं था, बल्कि चुनावी ढांचे में बदलाव की कोशिश थी, जो संविधान की मूल भावना को प्रभावित कर सकती थी। उनके अनुसार, विपक्ष ने मिलकर इस प्रयास को रोकने का काम किया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक रणनीतियों और मतभेदों का प्रतिबिंब है। एक ओर सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही थी, वहीं विपक्ष इसके क्रियान्वयन के तरीके और समय को लेकर सवाल उठा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक सहमति बनाना आसान नहीं है। यह मामला अब केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले चुनावों में भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

फिलहाल, महिला आरक्षण विधेयक का गिरना उन करोड़ों महिलाओं के लिए निराशाजनक माना जा रहा है, जो राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाने की उम्मीद लगाए बैठी थीं। हालांकि, सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगी और भविष्य में इसे फिर से लाने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।

अंततः, यह घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र के उस जटिल स्वरूप को दर्शाता है, जहां बड़े सामाजिक बदलावों के लिए केवल इच्छाशक्ति ही नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक सहमति भी उतनी ही आवश्यक होती है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या राजनीतिक दल इस मुद्दे पर कोई साझा रास्ता निकाल पाते हैं या यह बहस इसी तरह टकराव के बीच आगे बढ़ती रहेगी।

हर दशक में लंबी होती गर्मी, बदलता भारत का मौसम और बढ़ती चुनौतियां

नई दिल्ली से सामने आई एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रिपोर्ट ने भारत में बदलते मौसम के खतरनाक संकेतों को उजागर कर दिया है। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि भारत में गर्मी का मौसम अब केवल तीव्र ही नहीं, बल्कि लगातार लंबा भी होता जा रहा है। 1961 से 2023 तक के तापमान आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि विशेष रूप से 1990 के बाद से हर दशक में गर्मी औसतन छह दिन बढ़ती चली गई है।

यह बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर देश के जनजीवन, खेती, जल संसाधनों और पर्यावरण पर गहराई से दिखाई देने लगा है। पहले जहां गर्मी का एक तय समय होता था, अब वह धीरे-धीरे पूरे साल के मौसम चक्र को प्रभावित कर रही है। मौसम की पारंपरिक समझ बदल रही है और अब वैज्ञानिक तापमान के वास्तविक पैटर्न के आधार पर ही मौसम की परिभाषा तय कर रहे हैं।

इस साल के अनुभव ने इस शोध को और

भी प्रासंगिक बना दिया है। सर्दी का मौसम जल्दी समाप्त हो गया और पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य से काफी कम बर्फबारी हुई। इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि गर्मी ने अपेक्षित समय से पहले ही दस्तक दे दी। यह स्थिति न केवल आम लोगों के लिए असुविधाजनक है, बल्कि कृषि और जल प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस बदलाव का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ रहा है। फसलों के बोने और काटने का समय पारंपरिक रूप से मौसम पर आधारित रहा है, लेकिन जब मौसम ही अस्थिर हो जाए, तो खेती की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। किसानों को अब फसल चक्र में बदलाव करना पड़ सकता है, जिससे उत्पादन और आय दोनों पर असर पड़ने की आशंका है।

गर्मी के लंबे होने का एक और गंभीर परिणाम जल संकट के रूप में सामने आ रहा है। जब तापमान अधिक समय तक ऊंचा बना रहता है, तो जल स्रोत तेजी से सूखने लगते हैं। नदियों का जल स्तर घटता है और भूजल का दोहन बढ़ जाता है। दूसरी ओर, हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है, जो निचले इलाकों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।

शोध में यह भी सामने आया है कि 1990 से 2023 के बीच उत्तरी गोलार्ध की भूमि पर गर्मी की तीव्रता तीन गुना से अधिक तेजी से बढ़ी है। इसका असर भारत जैसे देशों में और भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। महानगरों में स्थिति और गंभीर है, जहां कंक्रीट और प्रदूषण के कारण 'हीट आइलैंड इफेक्ट' देखने को मिलता है। दिल्ली जैसे शहरों में गर्मी का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक महसूस किया जाता है।

बढ़ती गर्मी का सीधा असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और मजदूर वर्ग के लिए यह स्थिति अधिक खतरनाक होती जा रही है। लंबे समय तक उच्च तापमान में काम करना न केवल शारीरिक थकान बढ़ाता है, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करता है।

यह बदलाव केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे मानव गतिविधियों की भी बड़ी भूमिका है। औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण और जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ा रहे हैं, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। भारत भी इस वैश्विक समस्या का हिस्सा है और इसके प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता।

टीसीएस नासिक केस में बड़ा खुलासा, संगठित 'मॉड्यूल' की जांच तेज

नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) कार्यालय में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोपों ने देशभर में सनसनी फैला दी है। मामला अब केवल एक कंपनी या शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने कॉर्पोरेट कार्यस्थलों की सुरक्षा, कर्मचारियों के अधिकारों और संस्थागत जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) समेत संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग का यह कदम इस बात का संकेत है कि मामला केवल आपराधिक नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन से भी जुड़ा हुआ है।

इधर, देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीर बताते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार इसमें शामिल कथित 'मॉड्यूल' का पूरी तरह पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसे तोड़ने के लिए जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। उनका यह बयान इस मामले को और अधिक संवेदनशील और व्यापक बनाता है।

पुलिस ने जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जो मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटा है। अब तक कुल 9 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 8 महिला कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 6 पुरुष और एक महिला एचआर अधिकारी शामिल हैं। यह तथ्य इस बात को और गंभीर बनाता है कि आरोप केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि संस्थागत संरचना तक फैले हो सकते हैं।

जांच के दौरान फरार आरोपी निदा खान का नाम लगातार सामने आ रहा है। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिसमें अपने गर्भवती होने का हवाला दिया गया है। दूसरी ओर, उनके परिवार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक साजिश बताया है। उनका कहना है कि यह मामला किसी अन्य स्थानीय विवाद से ध्यान भटकाने के लिए खड़ा किया गया है।

मामले के सबसे चौंकाने वाले पहलुओं में पीड़ितों द्वारा लगाए गए आरोप हैं। शिकायतों में दावा किया गया है कि कुछ कर्मचारियों पर कार्यालय के भीतर नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया गया और उनके धर्म का अपमान किया गया। इसके अलावा, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। पीड़ितों का यह भी कहना है कि जब उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, तब भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

यह मामला केवल एक आपराधिक जांच नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े व्यापक सवाल उठाता है। कॉर्पोरेट कंपनियों में आंतरिक शिकायत समितियां (ICC) और अन्य सुरक्षा तंत्र मौजूद होते हैं, लेकिन यदि इन तंत्रों के बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

सामाजिक और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बेहद जरूरी होती है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न केवल दोषियों के लिए कड़ी सजा का मामला होगा, बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कार्यस्थल नीतियों में बड़े सुधार की आवश्यकता भी सामने आएगी।

फिलहाल, मुंबई और नासिक सहित कई स्थानों पर जांच जारी है। SIT टीम विभिन्न एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है और संभावित नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

यह पूरा घटनाक्रम एक चेतावनी भी है कि आधुनिक और संगठित कार्यस्थलों में भी यदि निगरानी और जवाबदेही मजबूत नहीं होगी, तो ऐसे गंभीर मामलों को रोका नहीं जा सकेगा। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों और अदालत पर है, जहां से इस मामले की असली तस्वीर सामने आने की उम्मीद की जा रही है।

तमिलनाडु में सियासी गर्मी चरम पर, डीएमके के 'क्लीन स्वीप' दावे ने बढ़ाया चुनावी रोमांच

चेन्नई से उठी एक राजनीतिक आवाज ने पूरे तमिलनाडु के चुनावी परिदृश्य को नई दिशा दे दी है। उदयनिधि स्टालिन द्वारा किया गया यह दावा कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) आगामी विधानसभा चुनावों में "क्लीन स्वीप" की ओर बढ़ रही है, अब केवल एक बयान नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का केंद्रीय बिंदु बन गया है। इस दावे ने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया है, बल्कि विपक्षी दलों को भी आक्रामक रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। उदयनिधि स्टालिन ने अपने चुनावी अभियान का विस्तृत उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने महज 16 दिनों में लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि पार्टी इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। उनके अनुसार, हर क्षेत्र में जनता की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है और लोगों में सरकार के प्रति विश्वास दिखाई दे रहा है। उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ केवल संख्या नहीं, बल्कि समर्थन का संकेत है, जो डीएमके के पक्ष में माहौल बनने की ओर इशारा करता है।

उदयनिधि स्वयं चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी सीट से मैदान में हैं, जो लंबे समय से डीएमके का मजबूत गढ़ रही है। लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी सरल नहीं मानी जा रही हैं। विपक्ष ने भी इस सीट सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में

अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रणनीतिक उम्मीदवार उतारे हैं। इसके बावजूद उदयनिधि का आत्मविश्वास यह दर्शाता है कि पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे और जनाधार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है।

तमिलनाडु की राजनीति ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय दलों के इर्द-गिर्द घूमती रही है, जहां वैचारिक और सामाजिक मुद्दे हमेशा प्रमुख रहे हैं। इस बार भी चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं है, बल्कि यह राज्य की सामाजिक-राजनीतिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है। डीएमके अपनी सरकार की योजनाओं, सामाजिक न्याय की नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता के सामने रखकर समर्थन जुटाने में लगी है।

वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। वे सरकार के दावों को चुनौती देते हुए बेरोजगारी, महंगाई, बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक मुद्दों को उठाकर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से चुनावी माहौल लगातार तीखा होता जा रहा है, जहां हर बयान और हर रैली का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है।

23 अप्रैल को एक ही चरण में होने वाला मतदान इस बार बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य के मतदाता न केवल अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनेंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि अगले पांच वर्षों में तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में जाएगी। 4 मई को होने वाली मतगणना के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या डीएमके का 'क्लीन स्वीप' का दावा हकीकत में बदलता है या विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर करने में सफल रहता है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, "क्लीन स्वीप" जैसे दावे चुनावी मनोविज्ञान का हिस्सा होते हैं। ऐसे बयान कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और मतदाताओं के बीच जीत का माहौल बनाने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन वास्तविकता अक्सर जमीनी समीकरणों, स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि पर निर्भर करती है। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि परिणाम किसके पक्ष में जाएंगे।

इस चुनाव में युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार और नए राजनीतिक विमर्श ने चुनावी रणनीतियों को बदल दिया है। डीएमके और विपक्ष दोनों ही इन नए माध्यमों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, जिससे चुनाव और भी प्रतिस्पर्धी हो गया है।

इसके अलावा, गठबंधन की राजनीति भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तमिलनाडु में अक्सर चुनाव परिणाम केवल एक पार्टी के प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि उसके सहयोगियों की ताकत पर भी निर्भर करते हैं। ऐसे में डीएमके का यह दावा कि वह अकेले दम पर क्लीन स्वीप करेगी, एक बड़ा और साहसिक बयान माना जा रहा है।

चुनावी रैलियों, रोड शो और जनसभाओं के बीच आम मतदाता अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान की उम्मीद भी लगाए बैठा है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दे अभी भी लोगों की प्राथमिकता में हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा दल इन मुद्दों को बेहतर तरीके से संबोधित कर पाता है।

उदयनिधि स्टालिन का यह बयान निश्चित रूप से चुनावी बहस का केंद्र बन चुका है। यह केवल एक राजनीतिक दावा नहीं, बल्कि डीएमके की रणनीति, आत्मविश्वास और चुनावी दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला हमेशा जनता के हाथ में होता है, और वही तय करेगी कि यह दावा सियासी नारा बनकर रह जाता है या ऐतिहासिक जीत में बदल जाता है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

नासिक यौन उत्पीड़न मामले से सुरक्षा खामियां उजागर

देश की एक प्रमुख आईटी कंपनी की नासिक शाखा में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयासों के चौंकाने वाले आरोप परेशान करने वाले हैं। निस्संदेह, यह प्रकरण बेहद गंभीर है और इन आरोपों ने कार्यस्थल की सुरक्षा जैसे नजरअंदाज किए जा रहे महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर देश का ध्यान आकर्षित किया है। यह आरोप है कि पुरुष कर्मचारियों का एक समूह महिला सहकर्मियों को निशाना बनाने के लिए एक 'संगठित गिरोह' की तरह काम कर रहा था। निश्चित रूप से यह घटनाक्रम कंपनी प्रबंधन की उस घोर लापरवाही को ही उजागर करता है जिस के चलते समय रहते इस तरह के यौन उत्पीड़न व धर्म परिवर्तन की कोशिशों पर अंकुश नहीं लग सका। यह विडंबना ही है कि मानव संसाधन प्रबंधक ने कथित तौर पर पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने से यह कहकर रोका कि –'ऐसी चीजें होती रहती हैं।' आक्षेप लगाया गया है कि इस प्रकरण में आरोपी का ही पक्ष लिया गया। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम कॉर्पोरेट जगत में व्याप्त विद्रूपताओं और एक गहरी तथा व्यापक विफलता की ओर ही इशारा करता है। जबकि दावा यह किया जाता रहा है कि कॉर्पोरेट जगत की प्राथमिकता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चत करना है। इसमें दो राय नहीं है कि जब यौन उत्पीड़न रोकथाम ढांचे को लागू करने के लिये जिम्मेदार उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों पर दुर्व्यवहार को सामान्य या मामूली बात समझने का आरोप लगता है, तो सारे संस्थागत सुरक्षा उपाय ध्वस्त हो जाते हैं। निर्विवाद रूप से यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है, जब पीड़ित महिला कर्मचारी को न केवल अपराधियों द्वारा बल्कि उनकी सुरक्षा का दायित्व संभालने वालों द्वारा भी चुप कराने के प्रयास किये जाते हैं। एक बार फिर से पुलिस के हस्तक्षेप और परामर्श के बाद ही कई पीड़ित महिला कर्मचारियों ने आगे आने का साहस जुटाया है। जिसके बाद ही मामले में प्राथमिकी दर्ज हो पायी है। बहरहाल, इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण को लेकर एक असहज करने वाला प्रश्न यह उठता है कि क्यों भय, सामाजिक कलंक अथवा संस्थागत उदासीनता के कारण देश भर के विभिन्न कार्यस्थलों में ऐसे कितने ही यौन उत्पीड़न के मामले उजागर नहीं हो पाते हैं? इसमें दो राय नहीं कि इस मामले में जांच बिना किसी पुर्वाग्रह के आगे बढ़नी चाहिए। निर्विवाद रूप से आईटी कंपनी के नासिक प्रकरण में सांप्रदायिक या राजनीतिक रंग देने का प्रयास इस संकट की मूल चिंताओं को धूमिल करने का जोखिम जरूर पैदा कर सकता है। निस्संदेह, ऐसी घटनाओं को धार्मिक या वैचारिक नजरिये से देखना कॉर्पोरेट जवाबदेही और लैंगिक संवेदनशीलता वाले सुधारों की तत्काल आवश्यकता से ध्यान भटका सकता है। इस संवेदनशील विषय पर नजर रखने वाले तर्क देते हैं कि उत्पीड़न को संप्रदाय विशेष के अपराध के रूप में देखने के बजाय, इसे एक अधिकारी द्वारा अपने अधिकार के दुरुपयोग के रूप में देखा जाना चाहिए, जो किसी भी संस्थान में पारदर्शिता और प्रवर्तन की कमी वाले वातावरण में ही पनपता है। इस विचलित करने वाले प्रकरण में अधिकारियों की प्रतिक्रिया, जिसमें एक विशेष जांच दल का गठन भी शामिल है, स्वागत योग्य है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में महिला आयोग द्वारा भी एक स्वतंत्र जांच की जा रही है, जो कि एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। हालांकि, कॉर्पोरेट जगत से जुड़े कार्यालयों में स्थायी परिवर्तन तभी संभव होगा जब कंपनियां ऐसे मामलों में 'शून्य सहिष्णुता' की घोषणा करेंगी। इसके साथ ही जरूरत इस बात की भी कि कार्यालयों में ऐसा निर्भयतापूर्ण वातावरण तैयार किया जाए कि कोई भी महिला कर्मचारी बिना डर के बोलने के लिये सशक्त बन सके। उन्हें सशक्त बनाने के लिये आंतरिक तंत्र को सक्रिय रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि कंपनियों का शीर्ष प्रबंधन गाहे-बगाहे यह पड़ताल करता रहे कि सर्वाधिकार प्राप्त कोई अधिकारी असीमित अधिकारों की आड़ में उत्पीड़न के अपवित्र खेल में शामिल तो नहीं है। एक पारदर्शी व सतर्क व्यवस्था भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा सकती है।

मनुष्यता का शोकगीत बनती महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा

> "जब स्कूल निशाना बनते हैं तो ज्ञान मरता है। जब अस्पताल मलबे में बदलते हैं तो करुणा दम तोड़ती है, और जब तेल-गैस संयंत्र जलते हैं तो जीवन का ईंधन समाप्त होता है। सच तो यह है कि यह केवल युद्ध की नहीं, मानवता की पराजय है।

धरती पर इंसानियत फिर लहूलुहान है। दुनिया बारूद की गंध में सांस ले रही है, बारूद के धुएं में बच्चों की हंसी, स्कूलों की घंटियां और अस्पतालों की शांति सब कुछ घुल गया है। अमेरिका, इस्राइल और ईरान के युद्ध ने सभ्यता के मुंह पर एक बड़ा काला धब्बा छोड़ दिया है। युद्ध के दौरान जिस तरह बमबारी हुई है उससे मची तबाही और राष्ट्राध्यक्षों के सनकभरे बयानों ने संवेदना की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। अब युद्ध केवल सीमाओं का नहीं रहा, वह विचारों, अर्थव्यवस्था और नैतिक मूल्यों पर भी आक्रमण कर चुका है। ईरान, अमेरिका, इस्राइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस-यूक्रेन, हर मोर्चे पर निर्दोषों का लहू बहा है और महाशक्तियां हथियारों के व्यापार में लिप्त हैं। यदि सभ्यता का अंत युद्ध की धूल और बारूदी धुएं में ही होना है, तो फिर विकास का अर्थ क्या रह जाएगा?

अमेरिका की एक मिसाइल ने ईरान के एक शहर में ऐसी तबाही मचायी कि लोगों की रूह कांप उठी, मानवता कराह उठी। दक्षिणी ईरान के मीनाब में एक नौसैनिक अड्डे के पास स्थित शजारेह तैय्येब प्राथमिक विद्यालय पर हुए मिसाइल हमले में 7-12 साल उम्र की 165 मासूम बच्चियां मारी गईं। इन छोटी बच्चियों के शव किसी भी नीति-निर्माता, किसी भी बयान या किसी भी धर्म के पक्ष में दिए गए तर्कों को झुठला रहे हैं।

उधर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध ने अमानवीयता का एक और अध्याय जोड़ दिया है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान की सरहद पर भी अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों पर बम बरसे हैं। पाकिस्तानी सेना ने पिछले महीने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ओमिद नशा मुक्ति अस्पताल पर हवाई हमला कर अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। हमले में करीब 400 लोगों की मौत हो गयी और सैकड़ों लोग घायल हुए। इसके अलावा भी रिहायशी इलाकों और स्कूलों पर हमले हुए हैं। इन घटनाओं ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर यह युद्ध किसके लिए है और किसके खिलाफ है? यह सिर्फ बच्चियों और मरीजों की मौत का आंकड़ा नहीं है अपितु मनुष्यता का शोकगीत है। ये घटनाएं इस सदी की सबसे बड़ी शर्म हैं जो मानवता और नैतिकता के माथे पर गाढ़ा धब्बा बनकर दर्ज हो चुकी हैं।

हास्यास्पद बात ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों इन हमलों से पल्ला झाड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो शुरू में एक बचकाना बयान देते हुए यहां तक कह दिया था कि स्कूल पर 'ईरान ने खुद बम गिराया' है। लेकिन बाद में राजनीतिक बचाव करते हुए कहा गया कि निशाना साधने में चूक हुयी है। उधर पाकिस्तान का अस्पताल पर हमले से इनकार भी उतना ही झूठा और खोखला है, जितना सूरज की रोशनी में अंधकार की बात करना। सवाल यह नहीं कि बटन किसने दबाया, सवाल यह है कि मरे कौन। उत्तर स्पष्ट है-बच्चे, बीमार, और निर्दोष नागरिक। राष्ट्राध्यक्षों की ज़िद, तानाशाही प्रवृत्ति और शक्ति की होड़ ने यह सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक युग में युद्ध अब सीमा की नहीं, बल्कि स्वार्थ, सनक और अहंकार की राजनीति है।

ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई तथा अनेक सैन्य कमांडरों के अमेरिका व इस्राइल के हमलों में मारे जाने के बाद ईरान बदले की आग में धधक रहा है। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही अमेरिकी सैन्य बेस वाले खाड़ी के मुस्लिम देशों पर भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किये हैं। इन हमलों में भी बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। इन देशों में नागरिकों की हर सुबह मौत के खौफ और रातें 'कल क्या होगा' की बेचैनी में कटी हैं। कोई भी दिशा सुरक्षित नहीं रही। बमों की दिशा बदल सकती है, पर दर्द का पता हर बार वही रहता है, आम आदमी के सिर तक। ईरान के हमलों ने यह जता दिया कि प्रतिशोध अब भूगोल नहीं देखता।

आज की दुनिया का सबसे भयावह दृश्य यह है कि युद्ध बढ़ रहे हैं, और समानांतर रूप से हथियार-व्यापार फल-फूल रहा है। इन युद्धों के बीच अमेरिका अनेक देशों को 'सुरक्षा' के नाम पर हथियारों की डील दे रहा है। यानी युद्ध जितना फैलता है, मुनाफ़ा उतना बढ़ता है। यह मानवता के नाम पर किया जा रहा एक ऐसा वैश्विक व्यापार है, जहां हर मौत एक बाजार का संकेत बन गयी है। प्रतिशोध के गलियारों में हर मौत एक आंकड़ा बन रही है। नैतिकता अब केवल भाषणों में बची है, शांति का धर्म पूंजी के आगे हार रहा है। जो देश 'मानव अधिकार' की रक्षा का दावा करते रहे हैं, वे ही अब मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध भी कोई अलग कहानी नहीं है। वहां भी लाखों सैनिक और हजारों निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं। कथित 'सुरक्षा' के नाम पर की गई हर बमबारी, सभ्यता के इतिहास में निरंतर कलंक जोड़ रही है। पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी यूरोप-तीनों मोर्चों पर एक जैसी तस्वीर है। महाशक्तियां सीधे या परोक्ष रूप से शक्ति-परीक्षण में जुटी हैं। तेल, भूमि, वर्चस्व और वीभत्स विचारधारा की राजनीति इंसानी जीवन पर भारी पड़ रही है।

अब ऐसा लगने लगा है कि यह युद्ध किसी राष्ट्र का राष्ट्र के विरुद्ध नहीं मानवता के खिलाफ है। जब स्कूल निशाना बनते हैं तो ज्ञान मरता है। जब अस्पताल मलबे में बदलते हैं तो करुणा दम तोड़ती है, और जब तेल-गैस संयंत्र जलते हैं तो जीवन का ईंधन समाप्त होता है। सच तो यह है कि यह केवल युद्ध की नहीं, मानवता की पराजय है। जब राष्ट्र अपने निर्णय मृत्यु के गणित पर तय करने लगते हैं, तो सभ्यता का विवेक मर जाता है। इन युद्धों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या विज्ञान, तकनीक और आधुनिकता का विकास हमें सच में बेहतर मनुष्य और अधिक संवेदनशील बना पाया है? या हम सिर्फ अधिक शक्तिशाली होकर अधिक निर्दयी हो गए हैं? संयुक्त राष्ट्र, जिसे कभी विश्व-जागरूकता का प्रहरी कहा जाता था, आज सिर्फ निंदा-प्रस्तावों की संस्था बनकर रह गया है। न कोई ठोस कार्रवाई, न प्रभावशाली हस्तक्षेप। उसकी चुप्पी मानो यह स्वीकार कर रही है कि मिसाइलों की मार और बमों का शोर अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बड़ा है।

प्रेरणा

अहंकार और वास्तविक वर्चस्व का मौन सत्य

एक शांत सरोवर में खिला कमल केवल एक फूल नहीं था, बल्कि वह उस मानवीय प्रवृत्ति का प्रतीक था, जो स्वयं को श्रेष्ठ मानने की लालसा में अक्सर अपने अस्तित्व के मूल स्रोत को ही भूल जाती है। उसने अपनी सुंदरता, अपनी कोमलता और अपने विशिष्ट स्थान को देखा और गर्व से भर उठा। उसके शब्दों में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि अहंकार झलक रहा था। उसने दिशाओं को नमन करने का आदेश दिया, मानो प्रकृति का समस्त संतुलन उसी के इर्द-गिर्द घूमता हो। यह दृश्य केवल एक फूल का घमंड नहीं था, बल्कि यह उस मनुष्य का प्रतिबिंब था जो थोड़ी-सी उपलब्धि के बाद स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है।

कमल की इस गर्वोक्ति को जब सूर्य ने सुना, तो वह भी अपने स्थान से विचलित हो उठा। उसने भी अपने महत्व का बखान करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यदि वह न होता, तो कमल का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। यह कथन अपने आप में सत्य था, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना कठिन है, लेकिन जिस तरीके से यह कहा गया, उसमें भी वही अहंकार झलक रहा था, जो कमल में था। यहाँ एक गहरा संकेत छिपा है—अक्सर जो व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली होता है, वह भी कभी-कभी अपने वर्चस्व को सिद्ध करने के लिए शब्दों का सहारा लेने लगता है, और यही उसकी गरिमा को कम कर देता है।

जब दिशाओं ने दोनों की बातें सुनीं, तो वे हंस पड़ीं। उनकी हंसी उपहास की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की अभिव्यक्ति थी, जिसे कमल और सूर्य दोनों भूल चुके थे। उन्होंने कहा कि वर्चस्व का वास्तविक स्थान वहां होता है, जहां उसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह वाक्य केवल एक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि एक गहरी जीवन-दृष्टि का सार था। सच्चा वर्चस्व, सच्ची महानता और सच्ची गरिमा कभी स्वयं को प्रमाणित करने की कोशिश नहीं करती। वह अपने अस्तित्व से ही प्रमाणित होती है।

मानव जीवन में भी यह सत्य उतना ही प्रासंगिक है। आज के समय में लोग अपनी उपलब्धियों, अपनी शक्ति और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में अधिक विश्वास करते हैं। सोशल मीडिया से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक, हर जगह स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ लगी हुई है। लोग यह भूल जाते हैं कि वास्तविक सम्मान मांगने या जताने से नहीं मिलता, बल्कि वह अपने आप अर्जित होता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में महान होता है, तो उसके कर्म, उसका व्यवहार और उसका दृष्टिकोण ही उसकी पहचान बन जाते हैं।

अहंकार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से दूर कर देता है। कमल यह भूल गया कि उसकी सुंदरता केवल उसकी अपनी नहीं, बल्कि उस सरोवर, उस जल और उस वातावरण का भी योगदान है, जिसमें वह पनपा है। सूर्य भी यह भूल गया कि उसकी शक्ति भी एक व्यापक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। जब हम अपने अस्तित्व को केवल अपने दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो हम उस समग्रता को खो देते हैं, जो हमें वास्तव में महान बनाती है।

यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति और सच्चा धर्म कभी शोर नहीं करते। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक आचरण नहीं, बल्कि वह सत्य है, जो जीवन को संतुलित और सार्थक बनाता है। जब कोई व्यक्ति या विचार वास्तव में धर्म पर आधारित होता है, तो उसे अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार के प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। लोग स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे स्वीकार करते हैं।

आज के युग में यह समझना और भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं, जहां बाहरी चमक-दमक और दिखावे को ही सफलता का पैमाना मान लिया गया है। लोग यह मानने लगे हैं कि जितना अधिक वे अपने बारे में बताएंगे, उतना ही अधिक उन्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। वास्तविक सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है, जो बिना किसी दिखावे के अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपने मूल्यों पर अडिग रहता है। कमल और सूर्य की कथा हमें यह भी बताती है कि तुलना और प्रतिस्पर्धा की भावना ही अहंकार को जन्म देती है। जब हम स्वयं की तुलना दूसरों से करते हैं, तब हमें अपनी श्रेष्ठता या हीनता का अनुभव होता है। लेकिन यदि हम अपने भीतर झांकें और अपने अस्तित्व को समझें, तो हमें यह अहसास होगा कि हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है और उसे किसी अन्य से श्रेष्ठ या हीन साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

वास्तविक वर्चस्व वह है, जो दूसरों को दबाने से नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। उसका प्रभाव उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से दिखाई देता है। वह किसी से नमन की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि उसके व्यक्तित्व के कारण लोग स्वयं ही उसे सम्मान देते हैं।

इस पूरी कथा का सार यही है कि हमें अपने जीवन में अहंकार के स्थान पर विनम्रता को अपनाना चाहिए। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि हम अपने गुणों को नकार दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें और यह समझें कि वे केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि अनेक परिस्थितियों और सहयोगों का भी फल हैं।

जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे भीतर एक गहरी शांति और संतुलन उत्पन्न होता है। तब हमें अपने वर्चस्व को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही उसका प्रमाण बन जाता है। यही वह अवस्था है, जहां सच्ची गरिमा जन्म लेती है और जहां से जीवन का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है।

नारी शक्ति का वंदन

भारतीय संसद तीन दिवसीय विशेष सत्र में एक ऐसे युगांतकारी विधेयक पर चर्चा कर रही है, जो विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार की यह पहल सभी दलों के समर्थन की उम्मीद रखती है, क्योंकि यह विधेयक केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया मात्र नहीं, बल्कि समाज के बुनियादी सोच को नया आयाम देने वाली एक ऐतिहासिक पहल है। सितंबर 2023 में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के रूप में जिस यात्रा का श्रीगणेश हुआ था, वह अब निर्णायक मोड़ पर है। यह अधिनियम सुनिश्चित करेगा कि भावी लोकसभा एवं विधानसभाओं में नारी शक्ति की पूर्ण सहभागिता हो और नीति-निर्धारण में उनका स्वर एक-तिहाई भागीदारी के साथ मजबूती से सम्मिलित हो।

प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। उन्होंने महिलाओं की गरिमा और उनके सशक्तीकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। मोदी सरकार ने महिलाओं के जीवन के हर चरण में उनके सशक्तीकरण के लिए योजनाओं का एक व्यापक तंत्र तैयार किया है, जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना ने बेटियों के प्रति सोच बदला। उनका आत्मविश्वास और अवसर, दोनों बढ़े। मुद्रा योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया। पीएम आवास योजना से घर की लक्ष्मी को घर का मालिकाना अधिकार मिला।

सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हुआ। पीएम उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली और जीवन स्तर सुधरा। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण से माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और सुरक्षित जीवन की नींव मजबूत हुई। पीएम मातृ वंदना योजना से गर्भवती माताओं को पोषण और आर्थिक सहारा मिला। तीन तलाक रोधी कानून से मुस्लिम महिलाओं को अन्याय से मुक्ति मिली। उनका आत्मसम्मान बढ़ा और उनके अधिकार मजबूत हुए। नल से घर तक जल पहुंचने से महिलाओं का जीवन सुगम हुआ तो लखपति दीदी योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ीं। ये सब महिला सशक्तीकरण के प्रति हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है।

नीति-निर्धारण में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के लिए प्रधानमंत्री जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हैं, वह केवल आश्वासन नहीं है। उनकी स्पष्ट दृष्टि है कि 2029 से संसदीय प्रणाली में महिलाओं की 33 प्रतिशत मौजूदगी रहे, वे सशक्त हों, नीति निर्धारण में उनकी सशक्त भूमिका हो और वे देश की मुखर आवाज बनें। यह संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ाने मात्र का प्रयास नहीं है, बल्कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक परंपरा और एक शब्द में कहें तो उस आधुनिक सनातनी विचार प्रणाली में एक शोधन है, जिसकी बुनियाद में गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधती, अपाला, घोषा, विश्ववारा, सुलभा, सीकता, शाश्वती आदि अनेक ऋषि-नारियों ने वेद संहिताएं रचने से लेकर जीवन के अनेक क्षेत्रों में अपनी सूक्ष्म दृष्टि, उदात्त चिंतन और विलक्षण मेधा का परिचय दिया। आधुनिक भारत के निर्माण की पृष्ठभूमि में जहां अहिल्याबाई जैसी उदार राजमहिषी ने प्रशासनिक कौशल और जनकल्याण के मानक स्थापित किए, वहीं झांसी की रानी ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणोत्सर्ग से विश्व इतिहास में भारतीय नारियों के बलिदान-भाव की मिसाल कायम की।

वर्तमान भारत के निर्माण में भी महिलाओं का योगदान अद्वितीय है। सावित्रीबाई फुले के समाज सुधार, डा. आनंदी गोपाल जोशी के चिकित्सा संघर्ष से लेकर 'मिसाइल वुमन' टेसी थामस के वैज्ञानिक पराक्रम तक हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। खेलों में पीवी सिंधु, मैरी काम, मिताली राज और साइना नेहवाल ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, तो कला और संगीत में लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी सुर साम्राज्ञियों ने अपनी स्वर साधना से विश्व में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यह सूची अनंत है, जो प्रमाणित करती है कि स्त्री शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में है।

विधायिका में महिला आरक्षण का निर्णय 'वैदिक गरिमा' और 'आधुनिक प्रगति' का सुंदर संगम है। इसमें 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास' की पवित्र भावना शामिल है। यह विधेयक उन करोड़ों माताओं-बहनों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने परिवार और समाज के निर्माण में स्वयं को खपा दिया। इसका क्रांतिकारी प्रभाव हमारे ग्रामीण भारत पर पड़ेगा, जहां महिलाएं अब नेतृत्वकारी भूमिका में उभरेंगी। उनकी सक्रिय भागीदारी सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा वातावरण बनाएगी, जहां बेटियां केवल सपने नहीं देखेंगी, बल्कि उन्हें साकार करने का सामर्थ्य और वैधानिक अधिकार भी रखेंगी।

महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार की मंशा पवित्र है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम किसी एक पार्टी के एजेंडे की नहीं, बल्कि सभी के प्रयासों की जीत है। क्रेडिट सभी दलों को है, जो पिछले तीन-चार दशकों से लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। संसद उत्तरदायी जनप्रतिनिधियों का मंदिर है। राष्ट्र की जनता उनकी हर गतिविधि और सरोकार को सूक्ष्मता से परखती है। सभी सांसदों से अपेक्षा है कि वे राष्ट्र के सामूहिक मन को समझें। आज समय की मांग है कि हम दलगत सीमाओं से ऊपर उठें। इस संस्था के सदस्य के नाते मेरी अपील है कि नारी शक्ति के सामर्थ्य और स्वावलंबन के 'अभिषेक अनुष्ठान' में सभी अपने समर्थन की आहुति दें। यह सामूहिक प्रयास ही यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य का भारत न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सामाजिक न्याय और नारी गौरव के मामले में भी विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। हमारा सामूहिक प्रयास ही समर्थ और सशक्त भारत के निर्माण में मातृशक्ति की निर्णायक भूमिका तय करेगा।

अभियान

चित्रकूट का दिव्य रामगिरी शक्तिपीठ: जहां आस्था, इतिहास और भगवान राम की तपस्या का अद्भुत संगम है

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां केवल पूजा नहीं होती, बल्कि वहां स्वयं दिव्यता का अनुभव होता है। चित्रकूट का रामगिरी शक्तिपीठ ऐसा ही एक स्थान है, जहां प्रकृति, भक्ति और इतिहास एक साथ मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करते हैं। यह स्थान केवल एक शक्तिपीठ नहीं, बल्कि वह भूमि है, जहां भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान समय बिताया, साधना की और देवी शक्ति की उपासना की। इस कारण यह स्थान केवल देवी भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि रामभक्ति का भी जीवंत प्रतीक बन गया है।

शक्तिपीठों की परंपरा का संबंध देवी सती की उस करुण कथा से जुड़ा है, जिसमें उनके शरीर के विभिन्न अंग पृथ्वी के अलग-अलग स्थानों पर गिरे और उन स्थानों पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए। कहा जाता है कि जब राजा दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर व्याकुल होकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, ताकि शिव का मोह भंग हो सके। जहां-जहां वे अंग गिरे, वहां दिव्य शक्ति का संचार हुआ और वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय बन गए। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है चित्रकूट का रामगिरी शक्तिपीठ, जिसे शिवानी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है।

मान्यता है कि इस पवित्र स्थल पर माता सती का दायां स्तन गिरा था, जो मातृत्व, करुणा और पोषण का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यहां स्थापित देवी को 'शिवानी' के रूप में पूजा जाता है। यहां भगवान शिव भी भैरव रूप में 'चंड' नाम से विराजमान हैं, जो इस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को और भी प्रबल बनाते हैं। इस शक्तिपीठ का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को और अधिक प्रमाणित करता है।

चित्रकूट का महत्व केवल शक्तिपीठ होने तक सीमित नहीं है। यह वह भूमि है, जहां भगवान श्रीराम ने अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा बिताया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के लगभग साढ़े ग्यारह वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए थे। इस दौरान उन्होंने न केवल तपस्या की, बल्कि यहां के प्राकृतिक वातावरण में रहकर जीवन के गहरे सत्य को भी आत्मसात किया। इसी अवधि में भगवान राम ने इस शक्तिपीठ में देवी की पूजा-अर्चना की, जिससे इस स्थान का महत्व और भी अधिक बढ़ गया।

चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित यह शक्तिपीठ एक अद्भुत शांति का अनुभव कराता है। मंदाकिनी नदी के निर्मल जल के पास बैठकर जब भक्त देवी की आराधना करते हैं, तो उन्हें एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं, मानो समय ठहर गया हो और भक्त सीधे त्रेता युग में पहुंच गए हों।

रामगिरी शक्तिपीठ का एक और विशेष पहलू यह है कि यहां रामनवमी का पर्व अत्यंत भव्यता के साथ मनाया जाता है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भगवान राम और देवी शक्ति के संगम का उत्सव होता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं और अपने जीवन में सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। यहां की आरती, भजन और वातावरण में गूंजती श्रद्धा की ध्वनि हर भक्त के मन को भावविभोर कर देती है।

हालांकि इस शक्तिपीठ को लेकर कुछ मतभेद भी देखने को मिलते हैं। कुछ लोग मैहर शारदा देवी मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं, जबकि कुछ श्रद्धालु चित्रकूट के इस स्थान को ही वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। यह मतभेद भारतीय धार्मिक परंपराओं की विविधता को दर्शाता है, जहां एक ही आस्था के कई रूप और व्याख्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इन मतभेदों के बावजूद चित्रकूट का यह स्थान अपनी दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है।

इस शक्तिपीठ के दर्शन मात्र से ही भक्तों को अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। लोग यहां आकर केवल पूजा नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की अशांति को भी शांत करने का प्रयास करते हैं। यह स्थान उन्हें एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नया विश्वास प्रदान करता है। यहां की हवा में एक अलग ही पवित्रता है, जो हर व्यक्ति के मन को छू जाती है।

चित्रकूट का यह शक्तिपीठ हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक अनुभव है, एक भावना है, जो हमें हमारे भीतर के ईश्वर से जोड़ती है। जब भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी इस स्थान पर आकर देवी की आराधना की, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति की उपासना हर युग में और हर रूप में महत्वपूर्ण रही है।

आज के आधुनिक युग में, जब जीवन की गति तेज हो गई है और मनुष्य अपने ही बनाए हुए जाल में उलझता जा रहा है, ऐसे में चित्रकूट जैसे स्थान हमें एक ठहराव देते हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। यह शक्तिपीठ हमें उसी शांति की ओर ले जाने का एक माध्यम बनता है।

अंततः, चित्रकूट का रामगिरी शक्तिपीठ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है, जहां आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम होता है। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता है, वर्तमान को समझने की शक्ति देता है और भविष्य के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यहां आकर व्यक्ति केवल देवी के दर्शन ही नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर के उस दिव्य तत्व को भी महसूस करता है, जो उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देता है। यही इस शक्तिपीठ का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी विशेषता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

युवा ऊर्जा से नए शिखर की ओर: मारवाड़ी युवा मंच सूरत में नई कार्यकारिणी का गठन

सूरत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मारवाड़ी युवा मंच एक बार फिर नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। मंच की सूरत शाखा की वार्षिक आम सभा इस वर्ष अत्यंत उत्साह, संगठनात्मक एकजुटता और भविष्य की स्पष्ट दृष्टि के साथ संपन्न हुई, जिसमें वर्ष 2026–2027 के लिए नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। इस अवसर पर अभिषेक खेतान को अध्यक्ष, सुषांत बजाज को सचिव और कौशल गोयल को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह चयन केवल पदों का वितरण नहीं, बल्कि संगठन के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

सभा का वातावरण पूरे समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहा। मंच के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और वरिष्ठजनों की उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया। यह केवल एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि संगठन के मूल्यों, उद्देश्यों और आने वाले समय की योजनाओं पर गहन विचार-विमर्श का मंच भी बनी।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभिषेक खेतान ने अपने संबोधन में जिस स्पष्टता और दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी, उसने उपस्थित सभी सदस्यों को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी उनके लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और नेतृत्व का अवसर है। उनके शब्दों में एक युवा नेता का आत्मविश्वास और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की झलक साफ दिखाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन की असली ताकत उसके सदस्य होते हैं, और सभी के सहयोग से ही मंच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।

उन्होंने अपने दृष्टिकोण को विस्तार देते हुए बताया कि आने वाले समय में मंच की गतिविधियों को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाया जाएगा। सामाजिक सेवा को केंद्र में रखते हुए विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जरूरतमंदों की सहायता जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंच केवल पारंपरिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप नए कार्यक्रमों और पहलों को भी अपनाएगा।

सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर भी उनकी सोच बेहद स्पष्ट रही। उन्होंने कहा कि समाज की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और उसे जीवित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस दिशा में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों, उत्सवों और परंपराओं को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे और अपनी विरासत को समझ सके।

संगठनात्मक विकास को लेकर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मंच को अधिक सक्रिय और सशक्त बनाने के लिए संरचना को मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए नए सदस्यों को जोड़ने, युवाओं को नेतृत्व के अवसर देने और कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनका मानना है कि जब युवाओं को जिम्मेदारी दी जाती है, तो वे न केवल संगठन को नई दिशा देते हैं, बल्कि उसमें नई ऊर्जा भी भरते हैं।

सभा में उपस्थित प्रांतीय अध्यक्ष अजय अग्रवाल, संरक्षक रंजीत चौधरी और अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि यह टीम संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अनुभव और युवा ऊर्जा का संयोजन ही किसी भी संस्था की सबसे बड़ी ताकत होता है, और मारवाड़ी युवा मंच सूरत शाखा इस संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है।

पूर्व अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी गरिमा प्रदान की। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए नई टीम को मार्गदर्शन दिया और यह आश्वासन भी दिया कि वे हर कदम पर संगठन के साथ खड़े रहेंगे। यह परंपरा दर्शाती है कि मंच केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह कार्य करता है, जहां हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण होता है।

इस अवसर पर यह भी महसूस किया गया कि आज के समय में सामाजिक संगठनों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में ऐसे मंच लोगों को जोड़ने, सहयोग की भावना बढ़ाने और समाज के कमजोर वर्गों तक सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं। मारवाड़ी युवा मंच ने अपने कार्यों के माध्यम से इस भूमिका को हमेशा निभाया है और भविष्य में भी इसे और मजबूत करने का संकल्प लिया गया है।

सभा के दौरान कई सदस्यों ने अपने सुझाव भी रखे, जिनमें संगठन की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने, नई परियोजनाएं शुरू करने और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बढ़ाने के प्रस्ताव शामिल थे। इन सुझावों को गंभीरता से लिया गया और नई कार्यकारिणी ने उन्हें अपनी आगामी योजनाओं में शामिल करने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम के अंत में एक सकारात्मक संदेश के साथ यह विश्वास व्यक्त किया गया कि नई टीम अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेगी। संगठन के सभी सदस्यों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे मिलजुलकर मंच को और अधिक सशक्त, सक्रिय और प्रभावी बनाएंगे।

इस पूरे आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब संगठन में एकजुटता, स्पष्ट दृष्टि और सेवा का भाव होता है, तो वह निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मारवाड़ी युवा मंच सूरत शाखा की नई कार्यकारिणी इसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जो आने वाले समय में न केवल संगठन, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है।

तपती धूप में मानवता की शीतल छांव: सूरत में “पानी की परब” बनी जीवनदायिनी पहल

सूरत की भीषण गर्मी जब अपने चरम पर पहुंचती है, तो सड़कों पर चलने वाला हर व्यक्ति तपते सूरज से राहत की तलाश में होता है। ऐसे कठिन समय में जब तापमान लोगों की सहनशक्ति को चुनौती देता है, तब कुछ पहलें सिर्फ सेवा नहीं बल्कि संवेदना का जीवंत उदाहरण बन जाती हैं। इसी मानवीय संवेदना को साकार करते हुए Indian Red Cross Society की गुजरात इकाई के मार्गदर्शन में सूरत में “पानी की परब” का शुभारंभ किया गया है, जो न केवल प्यास बुझाने का माध्यम है बल्कि समाज में सेवा और सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है।

यह पहल ऐसे समय में शुरू की गई है जब गर्मी का प्रकोप दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारी, राहगीर और जरूरतमंद लोग इस मौसम में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उनके लिए ठंडे पानी का एक घूंट भी किसी अमृत से कम नहीं होता। “पानी की परब” इसी जरूरत को समझते हुए एक सशक्त सामाजिक प्रयास के रूप में सामने आई है, जिसने सूरत के जनजीवन में राहत की एक नई उम्मीद जगा दी है।

इस सेवा अभियान को गुजरात रेड क्रॉस सोसायटी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत शुरू किया गया है। राज्य शाखा के मार्गदर्शन में चोर्यासी शाखा ने इस पहल को जमीन पर उतारते हुए इसे जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस पहल की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह निःशुल्क है और आने वाले तीन महीनों तक निरंतर जारी रहेगी। इसका उद्देश्य केवल पानी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि समाज में यह संदेश देना भी है कि कठिन समय में एक-दूसरे की मदद करना ही सच्ची मानवता है।

सूरत शहर में इस अभियान के तहत कई प्रमुख स्थानों पर जल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। बारडोली, मांडवी और अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ फूलपाड़ा बस स्टेशन रोड पर भी “पानी की परब” का शुभारंभ किया गया है। यहां से गुजरने वाले लोग जब ठंडे पानी की व्यवस्था देखते हैं, तो उनके चेहरे पर जो सुकून और संतोष दिखाई देता है, वही इस पहल की असली सफलता है। यह दृश्य अपने आप में यह दर्शाता है कि छोटी-सी सेवा भी कितनी बड़ी राहत बन सकती है।

कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने इस पहल को और भी विशेष बना दिया। रेड क्रॉस सोसायटी चोर्यासी शाखा के चेयरमैन डॉ. प्रफुलभाई शिरोया सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योग जगत से जुड़े लोग और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि इस मौके पर उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए अत्यंत आवश्यक और प्रेरणादायक बताया। उनका मानना है कि इस तरह की पहलें समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को बढ़ावा देती हैं, जो किसी भी सभ्य समाज की पहचान होती है।

“पानी की परब” केवल एक सेवा अभियान नहीं, बल्कि एक विचार है—एक ऐसा विचार जो यह सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह पहल हमें यह भी याद दिलाती है कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में कहीं न कहीं हम इंसानियत के मूल मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, और ऐसे में इस तरह के प्रयास हमें फिर से उन मूल्यों से जोड़ते हैं।

गर्मी के इस कठिन दौर में जब हर व्यक्ति अपने-अपने संघर्ष में व्यस्त है, तब “पानी की परब” जैसे अभियान यह संदेश देते हैं कि समाज में अभी भी संवेदना जीवित है। यह पहल न केवल प्यास बुझा रही है, बल्कि दिलों को भी जोड़ रही है। यह उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं।

इस अभियान की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि समाज के अन्य लोग और संगठन भी इससे प्रेरणा लें और आगे आकर इस तरह के प्रयासों में योगदान दें। यदि हर व्यक्ति अपने स्तर पर थोड़ी-सी भी जिम्मेदारी निभाए, तो समाज में बड़ा परिवर्तन संभव है। “पानी की परब” इसी परिवर्तन की एक शुरुआत है, जो आने वाले समय में और भी व्यापक रूप ले सकती है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि सूरत में शुरू हुई यह पहल केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा वही है, जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए और जो दूसरों के जीवन में राहत और खुशी का कारण बने। “पानी की परब” इसी भावना का जीवंत प्रतीक है, जो तपती धूप में मानवता की शीतल छांव बनकर उभर रही है।

जियो का महा-आईपीओ: भारतीय बाजार में नई आर्थिक क्रांति की आहट

नई दिल्ली। भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में एक बार फिर बड़ा मोड़ आने की तैयारी है, क्योंकि Reliance Industries अपनी डिजिटल इकाई Jio Platforms को शेयर बाजार में उतारने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। लगभग दो दशकों के अंतराल के बाद रिलायंस समूह की किसी प्रमुख इकाई का आईपीओ आने वाला है, और यह सिर्फ एक वित्तीय घटना नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह आईपीओ आकार और प्रभाव—दोनों के लिहाज से देश का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू बन सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) अगले महीने दाखिल किया जा सकता है। इस दस्तावेज में कंपनी के पूरे वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन को शामिल किया जाएगा, ताकि संभावित निवेशकों को एक व्यापक और स्पष्ट तस्वीर मिल सके। इसमें जियो के सब्सक्राइबर बेस, औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (ARPU), डेटा खपत, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और भविष्य की रणनीतियों जैसे अहम पहलुओं को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। यह वही आंकड़े हैं, जिन पर निवेशक सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि यही कंपनी की वास्तविक ताकत और संभावनाओं को उजागर करते हैं।

हालांकि, इस आईपीओ की टाइमिंग को लेकर पहले कुछ असमंजस देखने को मिला था। कंपनी ने प्रारंभिक योजना के तहत मार्च के अंत तक DRHP दाखिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों—विशेष रूप से ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव—के कारण बाजार में अस्थिरता बढ़ गई। ऐसे माहौल में बड़े आईपीओ को लॉन्च करना जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए रिलायंस ने समझदारी दिखाते हुए इसे कुछ समय के लिए टाल दिया। अब कंपनी अपने आगामी तिमाही नतीजों के बाद ही इसे फाइल करने की योजना बना रही है, ताकि निवेशकों को पूरी तरह अपडेटेड और मजबूत वित्तीय डेटा प्रस्तुत किया जा सके।

इस बहुप्रतीक्षित आईपीओ की तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी ने इसके प्रबंधन के लिए 19 बड़े निवेश बैंकों का कंसोर्टियम नियुक्त किया है। इनमें Kotak Mahindra Bank, Morgan Stanley, JM Financial, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America और Citigroup जैसे दिग्गज शामिल हैं। इतने बड़े स्तर पर निवेश बैंकों की भागीदारी इस बात का संकेत है कि यह आईपीओ न केवल भारत में बल्कि वैश्विक निवेशकों के बीच भी भारी आकर्षण का केंद्र बनने वाला है।

जियो प्लेटफॉर्म्स की कहानी अपने आप में भारतीय डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। 2016 में टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री के बाद जियो ने जिस तेजी से बाजार को बदल दिया, वह अभूतपूर्व है। सस्ते डेटा और व्यापक नेटवर्क कवरेज के दम पर जियो ने न केवल करोड़ों नए इंटरनेट यूजर्स को जोड़ा, बल्कि डिजिटल सेवाओं के एक विशाल इकोसिस्टम की भी नींव रखी। आज जियो केवल एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, बल्कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें OTT, क्लाउड सेवाएं, ई-कॉमर्स, फिनटेक और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि जियो का यह आईपीओ भारतीय शेयर बाजार के लिए एक “गेम चेंजर” साबित हो सकता है। इससे न केवल बाजार में तरलता बढ़ेगी, बल्कि टेक और डिजिटल कंपनियों के प्रति निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। इसके अलावा, यह आईपीओ भारतीय स्टार्टअप और टेक सेक्टर के लिए भी एक सकारात्मक संकेत देगा, जिससे भविष्य में और कंपनियां बाजार में उतरने के लिए प्रेरित हो सकती हैं।

एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जियो प्लेटफॉर्म्स में पहले से ही कई वैश्विक निवेशक हिस्सेदारी रखते हैं, जिनमें फेसबुक (अब मेटा), गूगल और अन्य बड़े फंड शामिल हैं। इन निवेशकों की मौजूदगी कंपनी की विश्वसनीयता को और बढ़ाती है। आईपीओ के जरिए आम निवेशकों को भी इस डिजिटल दिग्गज में हिस्सेदारी लेने का मौका मिलेगा, जो अब तक केवल बड़े संस्थागत निवेशकों तक सीमित था। हालांकि, इस आईपीओ के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं और निवेशकों की बदलती प्राथमिकताएं इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा, इतनी बड़ी राशि जुटाने वाले आईपीओ के लिए सही मूल्य निर्धारण (valuation) भी एक अहम चुनौती होगी। यदि कीमत ज्यादा रखी जाती है, तो निवेशकों की रुचि कम हो सकती है, और यदि कम रखी जाती है, तो कंपनी को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा।

अफवाहों के बीच हकीकत: देश में LPG-पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य, खपत में उछाल ने बढ़ाई चर्चा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच देश में ईंधन आपूर्ति को लेकर फैली आशंकाओं पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है—भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी भी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन की खरीद करें, क्योंकि घबराहट में की गई अतिरिक्त खरीद से कृत्रिम संकट पैदा हो सकता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव Sujata Sharma ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सप्लाई चेन पूरी तरह मजबूत और सक्रिय है, जिससे किसी भी तरह के व्यवधान की आशंका नहीं है। उनके अनुसार, देश के किसी भी हिस्से से ईंधन की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जो यह दर्शाता है कि आपूर्ति तंत्र पूरी तरह नियंत्रण में है।

हालांकि, इन सबके बीच एलपीजी की मांग में अचानक आई तेजी ने जरूर चर्चा को जन्म दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ऑटो एलपीजी की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। फरवरी महीने में जहां रोजाना लगभग 177 टन एलपीजी की बिक्री हो रही थी, वहीं अप्रैल में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 296 टन प्रतिदिन तक पहुंच गया है। यह वृद्धि लगभग 67 प्रतिशत के आसपास बैठती है, जो सामान्य परिस्थितियों में काफी बड़ी छलांग मानी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ती मांग के पीछे दो प्रमुख कारण हो सकते हैं—एक, गर्मी के मौसम में ईंधन की खपत में स्वाभाविक वृद्धि, और दूसरा, वैश्विक परिस्थितियों को लेकर लोगों में बनी अनिश्चितता। कई लोग एहतियात के तौर पर अतिरिक्त गैस या ईंधन खरीदने लगे हैं, जिससे खपत के आंकड़ों में तेजी से उछाल दिख रहा है। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि यह स्थिति किसी वास्तविक कमी का संकेत नहीं है, बल्कि केवल मांग के पैटर्न में बदलाव है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इस मांग का असर अलग-अलग स्तर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों—कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और पश्चिम बंगाल—में ऑटो एलपीजी की खपत तेजी से बढ़ी है। इन राज्यों में एलपीजी को एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में तेजी से अपनाया जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय लाभ के साथ-साथ लागत में भी कुछ हद तक राहत मिलती है। इसी के साथ सरकार ने दीर्घकालिक रणनीति के तहत पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू और औद्योगिक स्तर पर एलपीजी पर निर्भरता को कम करना है, ताकि ऊर्जा आपूर्ति अधिक स्थिर और टिकाऊ बन सके। आने वाले वर्षों में शहरों और कस्बों में PNG कनेक्शन बढ़ाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और विकल्प मिल सके।

पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर स्थिति स्पष्ट करते हुए भरोसा दिलाया है कि देश के समुद्री संचालन पूरी तरह सामान्य हैं। मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव Mukesh Mangal के अनुसार, पश्चिम एशिया क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और हाल के दिनों में किसी भी भारतीय जहाज से जुड़ी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। इसके अलावा, देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर कामकाज सामान्य रूप से जारी है और कहीं भी बाधा या अव्यवस्था की स्थिति नहीं है।

यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत देता है कि भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर पिछले वर्षों में जो रणनीतिक कदम उठाए हैं, वे अब असर दिखा रहे हैं। विविध स्रोतों से कच्चे तेल की खरीद, मजबूत रिफाइनिंग क्षमता, और बेहतर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क ने देश को इस स्थिति में पहुंचाया है कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद घरेलू आपूर्ति प्रभावित नहीं हो रही है।

इसके बावजूद, सरकार का मुख्य जोर इस बात पर है कि आम नागरिक संयम बनाए रखें। अफवाहों के चलते यदि लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने लगते हैं, तो इससे अनावश्यक दबाव बन सकता है। यही कारण है कि बार-बार यह अपील की जा रही है कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

कुल मिलाकर, जहां एक ओर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है, वहीं भारत के भीतर ईंधन आपूर्ति की स्थिति स्थिर और नियंत्रित दिखाई दे रही है। एलपीजी की बढ़ती मांग जरूर एक नया ट्रेंड दिखा रही है, लेकिन यह किसी संकट का संकेत नहीं, बल्कि बदलती उपभोक्ता आदतों और परिस्थितियों का परिणाम है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मांग को कैसे संतुलित करती है और ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कौन से नए कदम उठाए जाते हैं।

सोना-चांदी के वायदा में परस्पर विरुद्ध चाल: सोना वायदा 282 रुपये नरम, चांदी वायदा में 4860 रुपये का सुधार: क्रूड ऑयल 251 रुपये तेज

मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 10 से 16 अप्रैल के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 3584219.15 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 232611.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 3351605.81 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 37273 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में सप्ताह के दौरान कुल प्रीमियम टर्नओवर 49696.35 करोड़ रुपये का हुआ।

आलोच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 137703.49 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 152685 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 155065 रुपये के उच्च और 151255 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 153434 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 282 रुपये या 0.18 फीसदी की नरमी के साथ 153152 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 180 रुपये या 0.15 फीसदी औंधकर 122239 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 9 रुपये या 0.06 फीसदी गिरकर सप्ताह के अंत में 15323 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 150905 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 153500 रुपये के उच्च और 149733 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 310 रुपये या 0.2 फीसदी लुढ़ककर 151762 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 151567 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 154332 रुपये के उच्च और 150058 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 152366 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 277 रुपये या 0.18 फीसदी की गिरावट के साथ 152089 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

कमोडिटी वायदाओं में 232611 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 3351605 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 137703 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37273 पॉइंट के स्तर पर

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 242515 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 255735 रुपये और नीचे में 236452 रुपये पर पहुंचकर, 243768 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 4860 रुपये या 1.99 फीसदी बढ़कर 248628 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 4259 रुपये या 1.73 फीसदी की तेजी के संग 250195 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 4438 रुपये या 1.81 फीसदी तेज होकर सप्ताह के अंत में यह कॉन्ट्रैक्ट 250300 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

मेटल वर्ग में सप्ताह के दौरान 32981.20 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 75.75 रुपये या 6.35 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1268.7 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 9.4 रुपये या 2.84 फीसदी की मजबूती के साथ सप्ताह के अंत में 340.25 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 18.6 रुपये या 5.25 फीसदी बढ़कर 372.85 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 15 पैसे या 0.08 फीसदी घटकर सप्ताह के अंत में 194.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में सप्ताह के दारन 61906.39 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा 8516 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 9075 रुपये और नीचे में 8243 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 251 रुपये या 3.02 फीसदी की तेजी के संग 8576 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा सप्ताह के अंत में 251 रुपये या 3.02 फीसदी की बढ़त के साथ 8574 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा 251.6 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 255.9 रुपये और नीचे में 240.4 रुपये पर पहुंचकर, 250.6 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 4 रुपये या 1.6 फीसदी गिरकर 246.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 4 रुपये या 1.6 फीसदी लुढ़ककर 246.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में सप्ताह के दौरान मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा 1002 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 13.7 रुपये या 1.37 फीसदी औंधकर 984.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 81392.54 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 56310.95 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 25635.33 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 4645.07 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 106.83 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 2437.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 45339.42 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 16387.81 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 14.15 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन के वायदाओं में 4.02 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 7864 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 35545 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 13052 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 160756 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 29163 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 5899 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 14159 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 53742 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 9405 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 35831 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 36696 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 37396 के उच्च और 36696 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 920 पॉइंट बढ़कर 37273 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।

सूरत में नकली खाद्य पदार्थों का काला व्यापार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, जिससे जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। यह अब पूरे भारत में हो रहा है। असली के नाम पर नकली सामान का व्यापार आम बात नहीं है। बल्कि यह जनता को स्वस्थ रखने की बजाय, लोगों को बीमार करने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की एक सुनियोजित साजिश है। असली खाद्य पदार्थों में असली का स्वाद मिलाकर उन्हें असली जैसा दिखाने वाले नकली खाद्य पदार्थों को डिब्बों या पॉलीथीन की थैलियों में पैक करके, उन्हीं के लोगो, निशान और रंग की स्याही से बाजार में उतारा जाता है। इसी नकली सामान की बात करें तो, हाल ही में, कुछ दिन पहले, मथुरा सीमा पर सरकारी अधिकारियों ने कुछ लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और जेल भेज दिया। वे दो-तीन पानी से भरे टैंकरों में यूरिया खाद और एक निश्चित मात्रा में रसायन मिलाकर दूध को असली दूध जैसा बना रहे थे। यह पूरे देश में चर्चा का विषय है, लेकिन अगर हम सिर्फ सूरत की बात करें तो ऐसा लगता है कि सूरत अब नकली खाद्य पदार्थों का गढ़ बनता जा रहा है। क्योंकि एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) ने सचिन जीआईडीसी क्षेत्र में एक फैक्ट्री पर छापा मारा है। यह जानकर कोई भी आम नागरिक चौंक जाएगा। "सबका फूड्स" के नाम से चल रही इस फैक्ट्री में 15 किलो नकली "विदुर घी" बनाया जा रहा था, जिसमें सिर्फ 1 किलो शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा था और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा था।

देखिए, असली उत्पादों के नाम पर हज़ारों किलो नकली घी, नकली पनीर और नकली दूध बिकने की खबरें सामने आई हैं। अब सवाल उठता है कि जब सूरत समेत पूरे राज्य में इतने सारे नकली खाद्य पदार्थ फैले हुए हैं, तो सरकारी व्यवस्था में इन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए ज़िम्मेदार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य अधिकारी क्या कर रहे हैं? वे इस काले धंधे पर आंखें क्यों मूंद रहे हैं और उदासीनता क्यों दिखा रहे हैं? या उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? यही सोचने वाली बात है। इस पूरे नकली सामान के नेटवर्क के पीछे कोई बहुत ही शातिर खिलाड़ी ज़रूर होगा जो पर्दे के पीछे से

इन नए खिलाड़ियों को पूरी हिदायतें दे रहा है। यह शातिर खिलाड़ी पहले भी नकली सामान के धंधे में शामिल होने के आरोप में जेल जा चुका है और ज़मानत पर रिहा हो चुका है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण वह पर्दे के पीछे से ऐसे ही खेल खेलता रहता है, यही वजह है कि नकली सामान का यह रैकेट फल-फूल रहा है।

इस प्रकार, ग्राहकों को धोखा देने के लिए डिब्बों पर आकर्षक स्टिकर और मार्केटिंग के हथकंडे अपनाए गए। इन हथकंडों में, असली कंपनी के डिब्बों या सुमूल, अमूल, मधुरम आदि प्रसिद्ध डेयरी के असली पॉलीथीन पाउच को असली की तरह पैक करके, लोगो, कीमत आदि से मेल खाते हुए जनता को ठगा जाता था। इन प्रसिद्ध डेयरी के विक्रेताओं को ऊँचा कमीशन देकर, वे नकली सामान को असली बताकर प्रसिद्ध दुकानों में कम दामों पर बेचते थे, जिससे असली सामान की बिक्री को भी नुकसान होता था। दक्षिण गुजरात के कई व्यापारी, जो इस तरह का सामान खरीदते थे, इस नेटवर्क के सीधे संपर्क में थे और वर्षों से जनता को जहर परोस रहे थे। फिर यहाँ सवाल उठता है कि शहर के श्रमिक क्षेत्रों में, जहाँ श्रमिक आबादी रहती है और जो पहले से ही भीड़भाड़ वाले हैं, कई स्वस्थ और बीमार लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दुकानदारों पर भरोसा करते हैं और इन नकली सामानों को असली समझकर महंगे दामों पर खरीदते हैं। इस तरह वे गरीब लोग अनजाने में बीमारी को न्योता देते हैं। इसी तरह, जब कोई गरीब महिला अपने शरीर को ताकत और पोषण देने के लिए इस नकली घी या नकली पनीर का सेवन करती है, तो वह ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाती है। आधुनिक मशीनों के कारण अब पैकेजिंग में भी उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे उत्पाद, जिन्हें इस तरह पैक किया जाता है कि कोई भी व्यापारी असली डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग देखकर उन्हें पहचान न पाए, जाने-माने एजेंटों द्वारा बाजार में उतारे जा रहे हैं, जिससे प्रसिद्ध डेयरी कंपनियों को वित्तीय नुकसान हो रहा है।

पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें नकली घी को एक-दो किलो के डिब्बों में भरकर मशहूर डेयरियों में तस्करी करके पहुंचाया गया है। हाल ही में सचिन जीआईडीसी में पकड़ी गई नकली घी फैक्ट्री की मासिक आय मात्र 15 से 20 लाख रुपये थी। ज़रा सोचिए, ऐसे राष्ट्रविरोधी तत्व जो जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें मौत के कगार पर धकेल रहे हैं, और ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं कि एक कसाई भी अच्छा कहलाए, उन्हें किसी का डर क्यों नहीं है?

जनता के स्वास्थ्य की बात हो तो ऐसे तत्व भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो फिर इंसान को कैसे छोड़ेंगे? और इन काले व्यापारियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? कारण यह है कि इस मामले को देखने के लिए जिम्मेदार सरकारी व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और जिम्मेदार मंत्री शामिल हैं। लेन-देन की राजनीति के चलते शहर में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ऐसे फर्जी खेल चल रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सूरत शहर से हैं और जब उनकी आँखों के सामने नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री हो रही है, तो किसे दोषी ठहराया जाए? सूरत नगर निगम में जिम्मेदार अधिकारियों की कमी है। सूरत नगर निगम में स्वास्थ्य एवं अस्पताल उपायुक्त का पद स्वीकृत होने के बावजूद, जो शहर की जनता के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, एक साल से अधिक समय से खाली पड़ा है और व्यवस्था इसे भरने में भी विफल रही है। इस बीच, लोग नकली खाद्य पदार्थों को बेचकर मालामाल हो रहे हैं। ऐसे तत्वों को चीन या सऊदी अरब जैसे देशों की तरह तुरंत दंडित किया जाना चाहिए, इतनी कड़ी सजा कि वे फर्जी खबरों को ना कहना भी भूल जाएं, लेकिन पहल कौन करेगा?

सिंथेटिक दूध: भारतीय डेयरी के लिए एक अदृश्य और जानलेवा खतरा

सिंथेटिक दूध का बढ़ता चलन भारत की डेयरी उपलब्धि को खतरे में डाल रहा है, यह प्रकृतिक नहीं बल्कि मुनाफे के लिए रसायनों का मिश्रण है। FSSAI के अनुसार 25-33% नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरते, जो एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है।

घटक और स्वास्थ्य संबंधी खतरे

कैंसर और अंग क्षति का खतरा
डिटर्जेंट और यूरिया कैंसरकारी (carcinogenic) होते हैं और किडनी व लिवर को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं।

बच्चों के विकास में बाधा
मिलावटी दूध के सेवन से बच्चों में हार्मोनल असंतुलन और शारीरिक विकास रुकने जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

पहचान और बचाव के उपाय

गुण	प्राकृतिक दूध	सिंथेटिक दूध
गंध	कोई गंध नहीं	डिटर्जेंट जैसी सावुन की गंध
स्वाद	सुखद और मीठा	कड़वा स्वाद
बनावट	चिकनाइट रहित	रगड़ने पर साबुन जैसा चिकना अहसास

सुरक्षित खरीदारी के नियम
fssai केवल FSSAI प्रमाणित उत्पाद खरीदें
पुरानी या संदिग्ध पैकेजिंग से बचे (जैसे घी के 1L रिफिल पैक)

बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत ब्लाक के कारण अहमदाबाद मंडल से चलने/गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के उन्नयन एवं रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत गेरतपुर–अहमदाबाद खंड पर प्रीकास्टेड पोर्टल बीम की स्थापना हेतु दिनांक 19 अप्रैल 2026 को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके कारण निम्नलिखित ट्रेनें प्रभावित रहेगी।

शॉर्ट टर्मिनेशन / ओरिजिनेशन ट्रेनें

▸▸ट्रेन संख्या 20902 गांधीनगर केपिटल–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को 19.04.2026 को अहमदाबाद स्टेशन से प्रारंभ किया जाएगा तथा गांधीनगर केपिटल–अहमदाबाद के बीच निरस्त रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर केपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस को 19.04.2026 को वटवा स्टेशन पर समाप्त (शॉर्ट टर्मिनेट) किया जाएगा तथा वटवा–गांधीनगर केपिटल के बीच निरस्त

रहेगी।

निरस्त ट्रेनें (Cancelled Trains)

▸▸ट्रेन संख्या 69102 वटवा–वडोदरा मेमू 19.04.2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 69115 वडोदरा–वटवा मेमू 19.04.2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा–जामनगर इंटरसिटी 18.04.2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 22960 जामनगर–वडोदरा इंटरसिटी 19.04.2026 को निरस्त रहेगी।

आंशिक निरस्त (Partial Cancellation)

▸▸ट्रेन संख्या 19033 वलसाड़–अहमदाबाद गुजरात क्वीन 19.04.2026 को वडोदरा–अहमदाबाद के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

विनियमन (Regulation of Trains)

▸▸ट्रेन संख्या 19484 आसनसोल–अहमदाबाद एक्सप्रेस 19.04.2026 को वडोदरा मंडल में 1 घंटा 40 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

▸▸ट्रेन संख्या 12834 हावड़ा–अहमदाबाद एक्सप्रेस 19.04.2026 को वडोदरा मंडल में 1 घंटा 40 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

▸▸ट्रेन संख्या 22718 सिकंदराबाद–राजकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस : दिनांक 19.04.2026 को वडोदरा मंडल में लगभग 45 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

▸▸यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य अद्यतन जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय,अहमदाबाद में पक्षियों के लिए जलपात्र वितरण

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर "सेव अर्थ" अभियान के अंतर्गत दिनांक 17.04.2026 को मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, परिसर में एक सराहनीय पर्यावरणीय पहल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के मार्गदर्शन में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री सिद्धार्थ एवं उनकी टीम के सहयोग से मिट्टी के बर्तनों (जलपात्रों) का वितरण किया। इन जलपात्रों का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान पक्षियों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे हमारे पंख वाले मित्रों को राहत मिल सके।

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि "प्रकृति का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बढ़ती गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे प्रयास न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करते हैं।

यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं समाज को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध है।

इस कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री विकास गढ़वाल सहित मंडल के अन्य अधिकारी एवं रेल कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी उपस्थित जनों ने पर्यावरण संरक्षण एवं पक्षियों की सुरक्षा हेतु सामूहिक संकल्प भी लिया।

पालघर एवं उमरोली स्टेशनों के बीच गर्डर डी-लॉन्चिंग कार्य हेतु ब्लॉक

पालघर एवं बोईसर स्टेशनों के बीच स्थित मेसनरी आर्च ब्रिज के स्थान पर बॉक्स पुशिंग कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे द्वारा पालघर एवं उमरोली स्टेशनों के बीच आरएच गर्डर के डी-लॉन्चिंग हेतु 18 अप्रैल, 2026 को एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह ब्लॉक डाउन लाइन पर पालघर एवं उमरोली स्टेशनों के बीच 18 अप्रैल, 2026 को 02:10 बजे से 05:10 बजे तक लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 18/19 अप्रैल, 2026 की मध्यरात्रि में 23:15 बजे से 02:15 बजे तक अप एवं डाउन दोनों लाइनों पर भी ब्लॉक लिया जाएगा। इन ब्लॉकों के कारण कुछ ट्रेनें निरस्त, शॉर्ट टर्मिनेट तथा रेगुलेट की जाएंगी। प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

18 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करनेवाली निरस्त ट्रेनें:

1.दहानू रोड से 22:45 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93042 दहानू रोड – विरार मेमू पूर्णतः निरस्त रहेगी।

2.विरार से 21:05 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93039 विरार – दहानू रोड मेमू पूर्णतः निरस्त रहेगी।

3.विरार से 22:50 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 69173 विरार – दहानू रोड मेमू पूर्णतः निरस्त रहेगी।

शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें:

1.18 अप्रैल, 2026 को सूरत से 16:45 बजे प्रस्थान यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19102 सूरत – विरार एक्सप्रेस दहानू रोड स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

18 अप्रैल, 2026 को रेगुलेट होने वाली ट्रेनें:

1.ट्रेन संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनस – बरौनी अवध एक्सप्रेस 55 मिनट रेगुलेट होगी।

2.ट्रेन संख्या 19425 बोरीवली – नंदुरबार एक्सप्रेस 25 मिनट रेगुलेट होगी।

3.ट्रेन संख्या 12267 मुंबई सेंट्रल – हापा दुरंतो एक्सप्रेस 25 मिनट रेगुलेट होगी।

4.ट्रेन संख्या 22923 बांद्रा टर्मिनस – जामनगर हमसफर एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।

पश्चिम रेलवे का सांताक्रुज एवं गोरेगाँव स्टेशनों के बीच जम्बो ब्लॉक

पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रैक, सिगनलिंग तथा ओवरहेड उपकरणों के रख-रखाव हेतु रविवार, 19 अप्रैल, 2026 को सांताक्रुज एवं गोरेगाँव स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन फास्ट लाइनों पर 10:00 बजे से 15:00 बजे तक पाँच घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान फास्ट लाइन की सभी उपनगरीय ट्रेनें सांताक्रुज एवं गोरेगाँव स्टेशनों के बीच धीमी लाइन पर चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इस ब्लॉक के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ बोरीवली एवं अंधेरी सेवाएं गोरेगाँव तक हार्बर लाइन पर चलाई जाएंगी। प्रभावित सेवाओं की विस्तृत जानकारी उपनगरीय खंड के सभी स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

कच्छ में पानीपुरी बनी आफत, 100 लोग बीमार; स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर

कच्छ जिले के लोदाई इलाके में एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया, जब पानीपुरी खाने के बाद करीब 100 लोग अचानक बीमार पड़ गए। उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी शिकायतों के चलते लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ी और सभी प्रभावितों को भुज के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। राहत की बात यह है कि फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन घटना ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोदाई क्षेत्र में एक ही स्थान पर पानीपुरी खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। शुरुआत में कुछ लोगों को असहज महसूस हुआ, लेकिन देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग एक जैसे लक्षणों से पीड़ित होने लगे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित किया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई शुरू की।

जिला स्वास्थ्य विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया। बीमार लोगों को एंबुलेंस और अन्य साधनों के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की टीम ने सभी मरीजों का प्राथमिक उपचार शुरू किया और उन्हें निगरानी में रखा गया।

प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि पानीपुरी में इस्तेमाल किए गए पानी या मसालों की गुणवत्ता खराब हो सकती है। गर्मी के मौसम में खाद्य पदार्थों के जल्दी खराब होने की संभावना अधिक रहती है, खासकर यदि स्वच्छता के मानकों का पालन न किया जाए। इसी कारण फूड पॉइजनिंग के मामले अक्सर इस समय बढ़ जाते हैं।

घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके में खाद्य और पेय पदार्थों

की सप्लाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। विशेष रूप से बाहर से आने वाले फूड ट्रकों और अस्थायी स्टॉल्स की जांच के आदेश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी दूषित या असुरक्षित खाद्य पदार्थ लोगों तक न पहुंचे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि फूड पॉइजनिंग का सटीक कारण क्या था। विभाग ने यह भी साफ किया है कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि सड़क किनारे मिलने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि उपभोक्ताओं को भी सतर्क रहना चाहिए और केवल स्वच्छ व विश्वसनीय स्थानों से ही खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।

साथ ही, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे नियमित रूप से खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच करें और स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करें।

फिलहाल, कच्छ की इस घटना ने पूरे राज्य में सतर्कता बढ़ा दी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, लेकिन इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है।

सूरत नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा-कांग्रेस-आप के बीच टकराव, स्थानीय मुद्दों को लेकर मतदाताओं में भारी असंतोष

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कुछ वार्डों में भाजपा का दबदबा है और कुछ वार्डों में किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को प्रवेश करने से रोका जा रहा है, जिससे भाजपा विशेष रूप से चिंतित है। एक तरफ भाजपा विकास के खोखले वादे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं को कड़ाही में गंदे पानी की तरह गंदगी दिखाई जा रही है और पूछा जा रहा है, क्या हम यह पानी पीना चाहते हैं? कई दिनों से सड़कें नहीं बनी हैं, पीने का पानी साफ नहीं है, सीवेज ओवरफ्लो हो रहा है और गंदगी फैला रहा है। फिर भी अब तक आप कहां थे?

तीनों दलों के उम्मीदवारों से ऐसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे वे परेशान हैं। इसी वजह से इस चुनाव में भाजपा विपक्ष के फॉर्म रद्द करवाकर और निर्विरोध मैदान में उतरकर खुलेआम लोकतंत्र का नाश कर रही है और पूरी ताकत से वोटों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। तीनों दलों के उम्मीदवार अपने-अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मानो वे अकेले हों। ऐसे में देखना बाकी है कि सूरत नगर निगम की बागडोर जनता किसे सौंपेगी।

अब तक कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को भाजपा के गढ़ों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इन क्षेत्रों में भाजपा के नेता और मतदाता इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भाजपा के अलावा किसी अन्य पार्टी का उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। कोट क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता था। लेकिन इस गढ़ में भी अब मतभेद दिखने लगे हैं। इन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन मिल रहा है। लोग महंगाई और स्थानीय मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। भाजपा द्वारा हर साल करों में की जाने वाली बढ़ोतरी के कारण वोटों में अंतर आने की आशंका है। कहा जा रहा है कि भाजपा के अलावा अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों को कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अब लोग उम्मीदवारों से संपर्क कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा?

पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल चमका, 2025-26 में राजस्व और सेवाओं में बनाए नए रिकॉर्ड

पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले वडोदरा मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके के नेतृत्व में मंडल ने न केवल राजस्व वृद्धि के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की, बल्कि यात्री सुविधाओं को आधुनिक बनाने में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, वडोदरा मंडल ने इस वित्तीय वर्ष में 697.57 करोड़ रुपये का कुल यात्री राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के 638.68 करोड़ रुपये की तुलना में 8.34 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि न केवल बेहतर प्रबंधन का संकेत है, बल्कि यात्रियों की बढ़ती संख्या और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार को भी दर्शाती है।

मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नरेन्द्र कुमार ने बताया कि टिकट चेकिंग से प्राप्त राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2025-26 में टिकट जांच से 18.50 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.42 प्रतिशत अधिक है। यह दर्शाता है कि टिकट जांच अभियानों को अधिक सख्ती और प्रभावी तरीके से लागू किया गया।

इसके अलावा, नॉन-फेयर रेवेन्यू के तहत 7.23 करोड़ रुपये की आय दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के 6.92 करोड़ रुपये से 4.47 प्रतिशत अधिक है। वहीं, संड्री (विविध) राजस्व 13.89 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 13.57 करोड़ रुपये था।

अन्य राजस्व स्रोतों में भी वृद्धि देखने को मिली है। पार्किंग से 3.70 करोड़ रुपये की आय हुई, जो पिछले वर्ष 3.33 करोड़ रुपये से अधिक है। वहीं केटरिंग सेवाओं से 2.76 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया, जो पिछले वर्ष के 2.70 करोड़ रुपये से अधिक है। ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि मंडल ने आय के विभिन्न स्रोतों को बेहतर तरीके से विकसित किया है।

यात्री संख्या के मामले में भी वडोदरा मंडल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष 50.28 मिलियन यात्रियों ने मंडल की सेवाओं का उपयोग किया, जो पिछले वर्ष के 43.98 मिलियन यात्रियों की तुलना में 14.32 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि दर्शाती है कि यात्रियों का भरोसा रेलवे सेवाओं पर लगातार बढ़ रहा है।

सिर्फ राजस्व ही नहीं, बल्कि सेवा गुणवत्ता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रेल मदद शिकायतों में 112 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जबकि शिकायतों के निस्तारण समय में 60 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। यह उपलब्धि यात्रियों की संतुष्टि को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए वडोदरा स्टेशन पर डिजिटल लाउंज की स्थापना की गई है, जो अपनी तरह का अनोखा प्रयास है। यह भारतीय रेलवे में इस प्रकार का दूसरा डिजिटल लाउंज है, जहां यात्रियों को आरामदायक और तकनीक आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, रेल वन ऐप के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मंडल ने सक्रिय भूमिका निभाई है, जिससे यात्रियों को डिजिटल सेवाओं का अधिक लाभ मिल सके। वाणिज्य विभाग की इन उपलब्धियों के पीछे सघन और नियमित टिकट जांच अभियान, क्षेत्रीय पर्यवेक्षण में वृद्धि और सुदृढ़ सतर्कता जैसे कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही, यात्रियों को नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के लिए भी विशेष प्रयास किए गए।